सीएम योगी ने कहा- माहौल हमारे साथ, सभी 80 सीटें जीतना हमारा लक्ष्य...

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माहौल हमारे अनुकूल है, मोदी जी के 10 साल के काम, उनका नाम और नेतृत्व के साथ ही इस बार भगवान श्रीराम का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। ऐसे में इस बार 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है।

साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि हम अति आत्मविश्वास में ना रहें। हमें अपनी बूथ संरचना को और सुदृढ़ करते हुए जनता के साथ बेहतर संवाद को और अधिक प्रगाढ़ करना है। याद रहे राजनीतिक दलों के व्यवहार और कार्यपद्धति को जनता हमेशा नोट करती है और वक्त आने पर जवाब भी देती है। पार्टी का प्रत्याशी मतलब कमल का फूल, हमें बस यही मानकर चलना है।

बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित विकसित भारत मोदी की गारंटी पेटिका अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजिक कार्यक्रम को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र

सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित भाजपा नेताओं की मौजूदगी में सीएम योगी ने अभियान को शुरू किया। इसके अंतर्गत विकसित भारत मोदी की गारंटी पेटिका को भाजपा कार्यकर्ता घर-घर लेकर जाएंगे और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगेंगे। इसके अलावा पार्टी की ओर से मिस्ड कॉल अभियान की भी शुरूआत की गई है। इसमें 9090902024 पर मिस्ड कॉल के जरिए भी पार्टी के संकल्प पत्र के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने का एक ही तरीका है, हम अपने बूथ पर ध्यान दें। बीजेपी का कार्यकर्ता संकल्पित होकर आगे बढ़ेगा तो इस परिणाम को कोई रोक नहीं सकता। सच्चा लोकतंत्र वही है, जहां जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए होता है और जनता का शासन जनता के सुझावों से ही प्रारंभ होता है।

उन्होंने कहा कि बीजेपी घोषणा पत्र नहीं, बल्कि संकल्प पत्र के साथ जनता के पास जाती है। जनता को जनार्दन के रूप में मान्यता देकर हम उसकी उपासना और सेवा करते हैं। जनता की अपेक्षाओं को अपने जीवन का संकल्प मानकर अगले 5 साल की कार्ययोजना बनाते हैं और उसी पर कार्य करते हैं। जनता से सुझाव प्राप्त करने के इसी अभियान का शुभारंभ हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हमारे पास अपना तंत्र है, अपना स्वयं का संगठन है, विचार परिवार है, मोर्चे और प्रकोष्ठ हैं, शोध और प्रबंधन के प्रकोष्ठ हैं, इन सबके बावजूद जनता के सुझाव को हमने सर्वोपरि माना है। हम गांव-गांव में जाकर उनके महत्वपूर्ण सुझाव लेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम अपना संकल्प पत्र तैयार कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जानी जाती है। हमने जो कहा उसे मोदी-योगी के नेतृत्व में पूरा किया है। हमारा कोई हिडेन एजेंडा नहीं, बल्कि हमारा हरदम ओपेन एजेंडा होता है। धारा 370 हो या श्रीराममंदिर का निर्माण, ये सभी बातें हमारे संकल्प पत्रों का हिस्सा रही हैं। हमारे सभी संकल्पों को मोदी-योगी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र खत्म, पूछे गए 2,694 प्रश्न, 17 दिनों में हुई 12 बैठकें

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार आने के बाद पहला विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह सत्र 17 दिनों तक चला, जिसमें प्रदेश के बजट के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। विधानसभा का पहला बजट सत्र तय समय से दो दिन पहले बुधवार को सूचीबद्ध कामकाज पूरा करने के बाद, अध्यक्ष रमन सिंह ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। बजट सत्र समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के आखिरी सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही बजट सत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि सदन ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पारित कर दिया। इसके साथ ही बताया कि राज्य सरकार पिछले साल बेमेतरा जिले में सांप्रदायिक हिंसा में भुनेश्वर साहू की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा करेगी। डॉ रमन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित दुकानों की जांच के संबंध में (भाजपा विधायक) धरमलाल कौशिक के 6 फरवरी के तारांकित प्रश्न में, राज्य सरकार ने एक सदन समिति द्वारा जांच की सहमति दी है। उन्होंने इस सत्र को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि इस सत्र में 12 बैठकें हुईं और इस दौरान करीब 101.13 घंटे तक चर्चा हुई है।

संक्षिप्त समाचार

सर्वे में शिखर पर भाजपा, कांग्रेस को सिर्फ नुकसान ; राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों के नतीजे

जयपुर, एजेंसी। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच जी न्यूज और मैटराइज ने अलग-अलग राज्यों की लोकसभा सीटों को लेकर अपना ओपिनियन पोल जारी किया है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल में इन सभी सीटों को लेकर चौंकाने वाले अनुमान लगाए गए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अक्सर यह कहा जाता है कि यहां सत्ता विरोधी लहर काम करती है और हर चुनाव में सरकार बदलती है। ऐसा विधानसभा चुनाव में हुआ। राज्य की अशोक गहलोत सरकार विधानसभा चुनाव हार गई और बीजेपी ने यहां सरकार बनाई। भजन लाल शर्मा यहां मुख्यमंत्री बनाए गए।लेकिन अभी लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में राजस्थान में वोटरों के बदले मिजाज को देखना भी काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल इस ओपिनियन पोल में बताया गया है कि राजस्थान में बीजेपी को 66 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 28 फीसदी और अन्य के खाते में 6 फीसदी वोट जा सकता है। जी न्यूज के सर्वे में कहा गया है कि राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। इस सर्वे में कहा गया है कि राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं जबकि आईएनडीआईए गठबंधन के हिस्से में 1 सीट आ सकती है। राजस्थान में बीजेपी के क्लीन स्विप की संभावना है। राजस्थान के ओपिनियन में बताया जा रहा है कि कांग्रेस को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है।

आदिवासियों को सीएम साय ने गिफ्ट में दिया सोलर लाइट, अच्छा गांव योजना पर बोले यह सिर्फ शुरुआत

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर एयरपोर्ट में सुकमा से आए आदिवासियों से मुलाकात की है। इस बीच सीएम साय ने सुकमा के आदिवासियों को गिफ्ट के तौर पर सोलर लाइट दिया है। बतादें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर रवाना होने के लिए रायपुर विमानतल पहुंचे हुए थे।

उनके साथ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने आदिवासियों को सोलर लाइट की सौगात दी है। दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर के विमानतल में पत्रकारों से चर्चा में सीएम ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि पहली बार हुआ है कि सुकमा के सेंसेटिव क्षेत्र के आदिवासी छात्र यहां आए और विधानसभा की कार्यवाही देखी है। इनमें दो से तीन बच्चे जगदलपुर से आए थे। प्रदेश सरकार इन सभी को रायपुर के कई जगहों पर घुमा रही है। यह लोग पहली बार गांव से निकलकर ये देश दुनिया को देख रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है, हमने एक योजना अपना अच्छा गांव लांच किया है। इनके घर में बिजली, पानी सब काम हम प्राथमिकता से करेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, आपकी हर मांग पूरी की जाएगी। बता दें, भाजपा सहप्रभारी नितिन नबीन मैराथन बैठक में शामिल होने के लिए 28 फरवरी को छत्तीसगढ़ आए थे। अब वे इन सब के साथ दिल्ली के लिए निकल गए हैं।

एक और केंद्रीय एजेंसी ने उड़ाई नेताओं की नींद, लोकसभा चुनाव से पहले 600 अफसर खंगाल रहे बही-खाते

नईदिल्ली, एजेंसी। लोकसभा चुनावों से ऐन पहले केंद्र सरकार की एक और एजेंसी हरकत में है। इससे राजनीतिक दलों, नेताओं और ऐसे वित्तीय संस्थानों की नींद उड़ गई है जो काले धन के लेन-देन में शामिल रहे हैं। देश की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने करीब 600 अफसरों की एक टीम तैनात की है जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कॉपरेटिव बैंकों में कैश जमा और निकासी पर कड़ी नजर रख रही है। ये टीम चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए राजनीतिक हस्तियों और उनसे जुड़े लोगों के खातों पर नजर रख रही है। एजेंसी ने हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान ऐसे लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहे 12 कॉपरेटिव बैंकों की पहचान की है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईयू ने इस बार इनकम टैक्स, कस्टम, ईडी, राजस्व खुफिया निदेशालय और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के 600 अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसी उन सहकारी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रही है जो पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भारी मात्रा में हुए कैश लेनदेन को रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं। अधिकारी के मुताबिक, एजेंसी के राडार पर सभी बैंक हैं लेकिन कॉपरेटिव बैंकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। 12 कॉपरेटिव बैंकों में एजेंसी को कई गड़बड़ियां मिली हैं। बता दें कि अमूमन चुनाव आयोग चुनावों के दौरान ऐसे अवैध या संदिग्ध लेनदेन या भारी नकदी निकासी या सोने के लेनदेन और शराब बांटने जासे मामलों पर इनकम टैक्स, कस्टम, स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों से संपर्क रखती थी लेकिन इस बार एफआईयू ने पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कैश लेनदेन पर नजरें टेढ़ी कर ली हैं।

एफआईयू यानी (वित्तीय खुफिया इकाई) केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली एक खुफिया राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका मुख्य कार्य संदिग्ध लेनदेन, बड़े पैमाने पर नकद निकासी पर रिपोर्ट प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना और जरूरी होने पर उसे अन्य खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों से साझा करना है। एफआईयू रिपोर्टिंग संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर डेटा बेस भी स्थापित करता है और मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़े अपराधों से निपटने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय खुफिया जानकारी का संग्रह और साझाकरण का काम करता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेन्ड और टाइपोलॉजी पर रिसर्च और एनालिसिस भी करता है।

हिन्दुओं को सिर्फ मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने का ही अधिकार, नहीं बन सकते पुजारी ; हाईकोर्ट का फैसला

तिरुअनंतपुरम, एजेंसी। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिन्दुओं को सिर्फ मंदिर में प्रवेश करने और वहां पूजा करने का ही मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान हिंदू समुदाय के किसी भी सदस्य को मंदिरों में पुजारी (अर्चक) की भूमिका निभाने का कोई अधिकार नहीं देता है। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजितकुमार की खंडपीठ ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25(2)(बी) के तहत पूजा करने का अधिकार पूर्ण नहीं है और कोई भी भक्त यह दावा नहीं कर सकता कि मंदिर को 24 घंटे खुला रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी पुजारी की तरह पूजा कराने या बाकी धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत भी नहीं है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी भक्त यह दावा नहीं कर सकता कि उसे अनुष्ठान करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो केवल पुजारी ही कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने त्रावणकोर देवासम बोर्ड द्वारा जारी एक अधिसूचना को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की है। देवासम बोर्ड ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सबरीमाला अयप्पा मंदिर के मेलशांति (उच्च पुजारी) के पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार मलयाली ब्राह्मण समुदाय से होना चाहिए। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने त्रावणकोर देवासम बोर्ड की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 21 की पूरी तरह से अवहेलना है। याचिका में तर्क दिया गया था कि पुजारी के पद पर सिर्फ मलयाली ब्राह्मणों की नियुक्ति की अनिवार्य शर्त संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) और 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) का उल्लंघन है।

झारखंड : दूल्हे की अजीबोगरीब शर्त से टली शादी, बैरंग लौटी बारात

रांची, एजेंसी। वैवाहिक रस्म के दौरान दूल्हे की अजीबोगरीब शर्त की वजह से शादी टल गई और बारात को बैरंग लौटना पड़ा। वाकया झारखंड के गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र का है। बुधवार को गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र निवासी अंजनी कुमार की बारात केतार प्रखंड गई थी। बारातियों के स्वागत, जयमाल और द्वारपूजा के बाद जब दुल्हन के सिंदूरदान के रस्म का वक्त आया, तो दूल्हे ने शर्त रख दी कि वह लाइट बंद कर एकांत में यह रस्म पूरी करेगा। वर-वधू दोनों पक्ष के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी शर्त पर अड़ा रहा। अंतत : पंचायत बैठी और दोनों पक्षों की सहमति से शादी टाल दी गई। दूल्हा पक्ष को 5.13 लाख रुपए दुल्हन पक्ष को देना पड़ा।

मैं मजबूत प्रधानमंत्री के साथ मजबूत सरकार का मंत्री हूं - विदेश मंत्री जयशंकर

बेंगलुरु, एजेंसी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि उन्होंने यूक्रेन के साथ संघर्ष के दौरान मॉस्को पर लगे प्रतिबंधों के बीच रूसी तेल खरीदने पर कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि वह मजबूत प्रधानमंत्री के साथ मजबूत सरकार के मंत्री हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने हुबली के बीवीबी कॉलेज में यह बात कही, जहां उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों पर एक पुस्तिका जारी की। यह स्वीकार करते हुए कि भारत यूरोपीय देशों के बड़े दबाव में था, जिन्होंने रूस के साथ उसके तेल व्यापार को अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट दृष्टि थी, जिसने उस समय मदद की। मंत्री ने कहा, हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो बहुत स्पष्ट था - कि भारतीय उपभोक्ता का हित पहले आएगा। लोग कहते हैंकि आपने बहुत कड़ा रुख अपनाया। मैंने बहुत कड़ा रुख अपनाया, क्योंकि मैं एक मजबूत प्रधानमंत्री की सरकार का मंत्री हूं।पिछले दिनों, विदेश मंत्री जयशंकर ने चुटकी लेते हुए कहा था कि भारत की तेल खरीद यूरोप द्वारा एक दोपहर में की जाने वाली खरीद से कम है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल खरीदना दूसरों के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।इस महीने की शुरुआत में एक जर्मन दैनिक से बात करते हुए मंत्री ने रूस के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुष्टि करते हुए कहा था कि मास्को ने कभी भी नई दिल्ली के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से सदाबहार दोस्तों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की तेजी से जांच की जा रही है।भीड़ की तालियों और जयकारों के बीच, विदेश मंत्री जयशंकर ने पीएम मोदी की प्रशंसा की और कहा कि विदेश मंत्री बनना अच्छा है, लेकिन पीएम मोदी का विदेश मंत्री बनना बहुत अच्छा है।

पहली बार ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा, महज 3 महीने की बच्ची का किया था रेप और मर्डर

मुंबई, एजेंसी। ट्रांसजेंडर शख्स को अदालत ने तीन महीने की बच्ची से रेप और हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। यह देश का पहला मामला है, जब किसी ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा मिली है। मुंबई की सेशन कोर्ट के जज अदिति कदम ने यह फैसला सुनाया है। जज अदिति कदम ने फैसला सुनाते हुए कहा, उम्रकैद नियम है और मौत की सजा अपवाद है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में यह सजा मिलती है। यह अपराध ऐसा ही है। इस मामले में जिस तरह से अमानवीयता और बर्बरता दिखाई गई, उससे यह दुर्लभ केस बन जाता है। 24 साल के ट्रांसजेंडर पर नवजात बच्ची की किडनैपिंग, रेप और हत्या का केस चल रहा था। उसने मुंबई के कफे परेड इलाके में

2021 में इस वीभत्स घटना को अंजाम दिया था। ट्रांसजेंडर शख्स को अदालत ने जब सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह चुपचाप खड़ा रहा। वहीं घटना का शिकार हुई नवजात बच्ची के माता-पिता और परिवार के अन्य लोग फैसले के बाद अदालत पहुंचे। बच्ची के पिता ने कहा कि इस मामले में अदालत में तेजी से कार्यवाही आगे बढ़ी। हम इस फैसले से संतुष्ट है। जांच के मुताबिक बच्ची के जन्म के बाद ट्रांजसेंडर परिवार के पास गिफ्ट की मांग करते हुए पहुंचा था, जैसा कि आम रिवाज है। हालांकि परिवार ने उसे कोई शगुन देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर परिवार के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। इससे वह परिवार से चिढ़ने लगा था। एक दिन जब परिवार के लोग सो रहे थे, तब वह चोरी से घर में घुस आया। वह बच्ची को उठा लाया और उसका रेप किया। फिर उसकी हत्या कर दी और पास की एक नहर में फेंक दिया। पॉक्सो कोर्ट की जज ने कहा कि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। उन्होंने कहा कि यह ऐसा अपराध जिसने किसी भी बच्ची के माता-पिता को सदमे में डाल दिया। दोषी के दिमाग में किस हद तक जहर भरा था और उसकी क्या मानसिकता रही होगी, यह भी समझ से परे है। जज ने कहा कि यह मामला मौत की सजा के लिए उपयुक्त है। फैसले में जज ने कहा कि दोषी ने पहले से ही इस तरह के घृणित अपराध की योजना बना रखी थी।

भाजपा का आरोप: ममता राज में बंगाल सुरक्षित नहीं, मजबूरी में शेख शाहजहां को किया गया गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी एवं भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई विकल्प नहीं बचने पर उन्हें शेख शाहजहां को गिरफ्तार कराना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छिपने के 50 दिन बाद शेख शाहजहां की गिरफ्तारी से ममता बनर्जी की राजनीति पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल सुरक्षित नहीं है, खासकर महिलाएं, इसलिए उन्हें सत्ता से हटाने की जरूरत है।

अमित मालवीय ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा,पश्चिम बंगाल विधानसभा के पटल पर शेख शाहजहां का बचाव करने के बाद, ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, आखिरकार उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस को संदेशखाली में यौन हिंसा, हत्या, भूमि पर कब्जा और सरकारी अधिकारियों पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी।

मालवीय ने ममता बनर्जी की राजनीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा,शाहजहां की गिरफ्तारी, उसके छिपने के 50 दिन से अधिक समय बाद, प्रधानमंत्री के बंगाल पहुंचने से एक दिन पहले और कलकत्ता उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद की गई। भाजपा नेता ने कहा, शेख शाहजहां टीएमसी में अकेले अपराधी नहीं हैं। सौकत मोल्ला, जहांगीर खान आदि जैसे कई लोग हैं, जो परिणाम के डर के बिना, पश्चिम बंगाल पुलिस के समर्थन से आतंक का शासन चलाते हैं, क्योंकि वे ममता बनर्जी को वोट देते हैं। यह स्पष्ट है कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल सुरक्षित नहीं है, खासकर महिलाएं। उन्हें सत्ता से हटाने की जरूरत है।

शाहजहां शेख की कुंडली: मंत्री-विधायक से अधिक रुतबा, ड्राइवर से बना टीएमसी नेता

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने आज सुबह उत्तर 24 परगना के संदेशखाली के तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी में हो रही देरी के लिए विपक्षी पार्टी भाजपा ने लगातार ममता सरकार पर अपने नेता को बचाने के आरोप लगाया। सरकार पर बने रहे दबाव के बाद 5 फरवरी से लगातार फरार चल रहे शाहजहां शेख को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आइए टीएमसी के इस दबंग नेता के बारे में जानते हैं। कुछ स्थानीय टीएमसी नेताओं से बातचीत के बाद संदेशखाली हिंसा के कथित मास्टरमाइंडके बारे में पता चला है। उन्होंने कहा कि 45 साल के शाहजहां का सियासी उत्थान जबरदस्त रहा है। पश्तिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार को हटाकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार बनने के बाद वह 2013 में

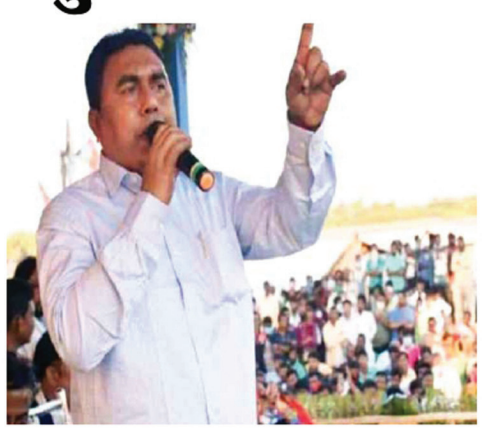

पार्टी में शामिल हो गए। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि शाहजहां अपने शुरुआती दिनों में संदेशखाली और सरबेरिया में कभी ड्राइवर और कभी-कभी सहायक के रूप में काम करता था। वह अपने मामा मुस्लिम शेख की छत्रछाया में पला-बढ़ा। उसके मामा पंचायत स्तर के सीपीआईएम नेता थे।

मछली के कारोबार में एंट्री : उसके गांव के एक व्यक्ति ने कहा, शाहजहां ने धीरे-धीरे मछली व्यापार में प्रवेश किया और क्षेत्र में मछली फार्मों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता गया उन्होंने गांव के युवाओं को शामिल करते हुए अपनी सेना भी बनानी शुरू कर दी। वह स्थानीय पार्टी नेताओं के भी संपर्क में रहते थे और चुनावों के दौरान उनकी मदद करते थे।

मंत्री-विधायक से अधिक रुतबा : पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता ज्योति प्रिया मल्लिक ने उनकी लोकप्रियता और उनकी शक्ति को पहचाना। आपको बता दें कि मल्लिक अब करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। एक ग्रामीण ने बताया, मल्लिक के करीबी सहयोगी माने जाने वाले शाहजहां 2013 में टीएमसी में शामिल हुए। तब से उन्हें पार्टी में काफी लोकप्रियता मिली। वह कई विधायकों और मंत्रियों से अधिक शक्तिशाली थे। उनका दबदबा ऐसा था कि 5 जनवरी को उनके घर की तलाशी लेने आए ईडी अधिकारियों पर 800-1000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। तीन अधिकारी घायल हो गए। इसके बाद से शाहजहां फरार चल रहा था।

पुलिस भी शाहजहां के पास जाने को बोलती : एक पुलिस अधिकारी ने कहा, उनका प्रभाव इतना था कि अगर कोई भी ग्रामीण टीएमसी के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाता था, तो पुलिस उसे शाहजहां से संपर्क करने की सलाह देती थी। वह भाई के नाम से मशहूर थे। राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने इस सप्ताह की शुरुआत में कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि पिछले चार वर्षों में उनके खिलाफ 43 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने 42 मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है तो कुछ में उसे फरार दिखाया गया है। चुनावी हलफनामें से पता चलता है कि शेख शाहजहां की वार्षिक आय लगभग 19.8 लाख रुपये है। बैंक में 1.9 करोड़ से अधिक जमा है। वह तीन बच्चों के पिता हैं। उनके पास लगभग 43 बीघा जमीन और सरबेरिया में एक घर है। घर की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है। उनके पास कम से कम 17 बाइक हैं।